



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 8, 1965 (वैशाख 18, 1887)

No. 19]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1965 (VAISAKHA 18, 1887)

इस भाग में मिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 21 अप्रैल 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 21st April 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
46	No. D-28 ITC(PN)/65, dt. 21st April, 1965	Ministry of Commerce	Import Policy for Newsprint of White Printing paper.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

CONTENTS

पृष्ठ Pages	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 251	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 13
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 353	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 225
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अभ्यादेश और विनियम —
	भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें —

	पृष्ठ Pages		पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	739	भाग III—खंड 2—एकस्व-कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	159
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	1599	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	33
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	12	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2389
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	293	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	99
		पूरक सं० 19—	
		1 मई, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	617
		10 अप्रैल, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	29
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	251	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1599
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	125
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	13	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	293
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	225	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	159
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	33
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2389
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	739	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	99
		SUPPLEMENT No. 19—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 1st May 1965	617
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 10th April 1965	629

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1965

सं० 6/1/65 सी० एस० (ए०)—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में खाली जगहों को भरने के लिये दिसम्बर 1965 में संच लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिये प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

- (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा-सहायक ग्रेड,
- (ii) भारतीय विदेश सेवा (बी०)-ग्रेड IV (सहायक),
- (iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड IV (सहायक), और
- (iv) भारत के हाई कमिशन, लन्दन में स्थानीय संवर्ग (कंडर) में कनिष्ठ सहायक के पद ।

नोट :—इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उक्त सेवाओं/पदों के अतिरिक्त किन्हीं ऐसे कार्यालयों में भी सहायकों के पदों पर कुछ नियुक्तियां की जा सकती हैं, जो कि उनमें से किसी भी सेवा के क्षेत्र में नहीं आते, जैसे—चुनाव आयोग, पर्यटन विभाग, समदीय कार्य विभाग, खुफिया ब्यूरो ।

2. संच लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

3. उम्मीदवार को या तो—

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा, या
- (ग) नेपाल की प्रजा, या
- (घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूलतः भारत में उत्पन्न ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान से प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो ।

परन्तु, ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटिया के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से लेकर केवल एक साल के लिये मान्य होगा । उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों से पात्रता प्रमाणपत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो और जो तब से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं ।

(ii) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो और संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो ।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल में कोई भंग (ब्रेक) नहीं हुआ है । लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में भंग हुआ हो और उसने 26 जनवरी 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो या शुरू कर सके तो उसे भी औरो की तरह पात्रता प्रमाणपत्र देना होगा ।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटि के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (बी०)-ग्रेड IV में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिये पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिये जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है ।

4 जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का न हो या पांडिचेरी मंध राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या अडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी न हो, या भारत के भूतपूर्व पुर्तगाली राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव का निवासी न हो या श्रीलंका से प्रत्यावर्तित न हो या पूर्वी अफ्रीका के केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ टान्ज़ानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) का प्रव्रजक न हो उसे इस परीक्षा में अधिक-से-अधिक दो बार बैठने दिया जाएगा । यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू है ।

नोट 1 :—यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिये यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार उक्त परीक्षा के अंतर्गत आनेवाली सब सेवाओं/पदों के लिये बैठ चुका है ।

नोट 2 :—यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो, किन्तु पहली अगस्त 1965 को किसी भी हालत में उसकी आयु पूरे 24 साल की न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त 1941 से पहले और पहली अगस्त 1945 के बाद न हुआ हो ।

(ख) ऊपर बताई गई ऊपरी आयु-सीमा में इस प्रकार छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक ;

(ii) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक चार वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार भारत कानागरिक हो और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपोर्ट्रिट) हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार भारत के भूतपूर्व पुर्नगाली राज्य-क्षेत्र (गोआ, दमन और दीव) का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिमजाति का हो तथा पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक; और

(viii) यदि उम्मीदवार भारत में मूलतः उत्पन्न व्यक्ति हो और उसने पूर्वी अफ्रीका के देशों केनिया, युगान्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ टांज़ानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों को छोड़ कर और किसी भी हालत में ऊपर निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती है।

6. (क) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए, या उसमें परिशिष्ट I-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए।

(ख) विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसमें उक्त योग्यता न हो, शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों में योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों जिन्हें परिशिष्ट I में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदनपत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदनपत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसा उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हो तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाएगी; और यदि वह उक्त परीक्षा को पास करने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करता तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

7. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवन पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवन रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवन रहने की अवधि में किए जाने के कारण असम्य (वायड) हो जाता है, उसे उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति का जिनके लिये इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और वह उस पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण असम्य (वायड) हो जाए कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति की, जिनके लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और वह उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) विवाहित महिला उम्मीदवार आम तौर पर भारतीय विदेश सेवा (बी०) के ग्रेड IV में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगी। इस ग्रेड की अविवाहित महिला को अपना विवाह करने से पहले सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। विवाह होने के बाद किसी भी समय यदि सरकार को यह संतोष हो जाए कि उसकी पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि उनके कारण सेवा के एक सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को उचित रूप से और दक्षतापूर्वक पूरा करने में बाधा पड़ सकती है, तो उसे सेवा से त्याग-पत्र देने के लिये कहा जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक न निभा सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किये जाने की सम्भावना हो।

10. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध I में निर्धारित फीस देनी होगी। उक्त अनुबंध में बताई गई मात्रा को छोड़ कर न तो फीस की वापसी की किसी प्रार्थना पर विचार किया जाएगा और न ही उक्त फीस किसी दूसरी परीक्षा या चुनाव के लिए आरक्षित (रिजर्व) की जा सकती है।

14. आवेदन-पत्र में मांगी गई सिफारिशों को छोड़ कर किसी और सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई उम्मीद-

बार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारों के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है।

15. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई छेड़ की गई है या कोई ऐसी बात लिखी है या गलत है या झूठी है या कोई नथ्य छिपाया है या परीक्षा में बैठने के लिये किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दाखिल अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकता है—

(क) साथ ही, उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये —

(i) आयोग उम्मीदवारों के चुनाव के लिये ली जान वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक रक्खता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी खाली जगहें आरक्षित की जाएंगी जितनी कि सरकार तय करे।

17. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप में दिए गए कुल प्राप्तांक के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकालने पर जितनी अनाक्षत खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवार योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा में योग्य माने गए हों।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दे तो उस सेवा/पद में, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित खाली जगहों पर उसकी नियुक्ति की मफारिश की जाएगी।

नोट 1 —आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताई गई पसंदों के क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (देखिए—आवेदन-पत्र का खाना 27) लेकिन उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा में/ऐसे किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिये उसकी परीक्षा ली गई हो।

नोट 2 —हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा।

18. नियुक्तियों दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

19. उम्मीदवारों को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोग द्वारा ली जाने वाली टाईपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो

वे सहायक-ग्रेड में आगे वेतन-वृद्धि पाने तक अधिकारी न होंगे, जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर ले या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए, और परीक्षा पास कर लेने पर या उसमें छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा, कि उनकी वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी। परन्तु, जितनी अवधि के लिये वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी०) में सहायकों और भारत के हाई कमिशन, लन्दन, में “स्थानीय संवर्ग (कैंडर)” में कनिष्ठ सहायकों के पदों तथा भारत के चुनाव आयोग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट III में संक्षेप में दी गई हैं।

के० त्यागराजन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
भारतीय विश्वविद्यालय :

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय, जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किये गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (1956) की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित संस्थाएं।

बर्मा के विश्वविद्यालय :

रगून विश्वविद्यालय।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिबरपूल, लंदन, मंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय :

एडिन्बरो, एडिनबरा, ग्लासगो और सेट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय :

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कॉलेज), नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बैलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय, राजशाही विश्वविद्यालय।

परिशिष्ट I—क

भारत सरकार ने नीचे लिखी योग्यताओं की उनमें से प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान की है :—

योग्यता का विवरण

समकक्ष मान्य उपाधि

- | | |
|--|--|
| 1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी का “अलंकार” | कला स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स) |
| 2. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का जामिया सन्दी | —वही— |
| 3. काशी विद्यापीठ बनारस का “शास्त्री” | —वही— |
| 4. फ्रांसीसी परीक्षा “बकालाउरे” (Baccalaureat) | कला स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स) |
| 5. फ्रांसीसी परीक्षा “प्रोपेदेतिक” (Propedeutique) | कला या विज्ञान स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स और साइंस) |

6. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद से ग्राम-आर्ट्स) सेवाओं में डिप्लोमा कला स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
7. विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्रामसेवा डिप्लोमा कला स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
8. अश्विनी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से वाणिज्य में डिप्लोमा वाणिज्य स्नातक (बैचलर ऑफ कॉमर्स)
9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा यथास्थिति, सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिग्री
10. भारतीय खान और अनुप्रयुक्त भूविज्ञान विद्यालय, धनबाद से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा खनन में विज्ञान आनर्स डिग्री का स्नातक
11. श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी को "उच्च पाठ्यक्रम" यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। कला या विज्ञान स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑर साइंस)

ध्यान दीजिए—(i) ऊपर की मद 1 से 3 में उल्लिखित योग्यताओं की मान्यता 17 सितम्बर 1965 तक रहेगी।

(ii) ऊपर की मद 4 में उल्लिखित योग्यता की मान्यता अनंतिम है।

परिशिष्ट II

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घंटे
2. सामान्य अंग्रेजी	200	3 घंटे
3. अंकगणित	100	2 घंटे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है	100	2 घंटे

2. परीक्षा का विषय-विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।

3. उम्मीदवार प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 4 का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं।

प्रश्नपत्र 2 और प्रश्नपत्र 3 का उत्तर उभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में देना होगा।

नोट 1 :—यह विकल्प पूरे प्रश्नपत्र के लिये होगा, न कि उसी प्रश्नपत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिये।

नोट 2 :—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के खाना 7 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए; नहीं तो, यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अंक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिये गए अंकों में से आयोग द्वारा निर्धारित अंक इसलिये काट लिए जाएंगे कि वहाँ कोरे सतही ज्ञान का उसे लाभ न मिल जाए।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत काट लिये जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, ताल और माप की मैट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है। प्रश्नपत्रों में यथावश्यक मुद्रा, ताल और माप की मैट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अनुसूची

परीक्षा का विषय-विवरण

1. निबंध :

दिए गए कुछ विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा।

2. सामान्य अंग्रेजी :

(i) सार-लेखन और मसौदा-लेखन : अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिये प्रश्न पूछे जाएंगे। आग तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिये अंश (पैसेज) दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्तों, जापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा वाक्यांशों के मुहावरोंदार प्रयोग और सामान्य लुटियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

(iii) शब्द भेद (पार्ट्स ऑफ स्पीच), वाक्य विश्लेषण, वाक्यरचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट एण्ड इन्डायरेक्ट स्पीच)।

नोट :—प्रश्नपत्र 2 में सार-लेखन के लिये 75 अंक, मसौदा-लेखन के लिये 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिये 50 अंक होंगे।

प्रश्नपत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा की योग्यता की परीक्षा करना है। वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा।

3. अंकगणित :

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों को पढ़ना और आंकड़ों का सारणीकरण।

प्रश्नों का उद्देश्य यह मालूम करना है कि उम्मीदवार कार्य को शीघ्रता से, ठीक-ठीक और समझ-बूझ के साथ कर सकते या नहीं।

4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे

साधारण पढ़े-लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्नपत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकता है।

परिशिष्ट III

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

1. (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा :-

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :-

- | | |
|--|--|
| (1) सेलेक्शन ग्रेड (उप-सचिव या समकक्ष) | रु० 1,100-50-1,300-60-1600-100-1,800 |
| (2) ग्रेड (अवर सचिव या सम-कक्ष) | रु० 900-50-1,250 |
| (3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड | रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900 |
| (4) सहायक ग्रेड | रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 |

नोट :- जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम-से-कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिबीक्षा पर रखा जाएगा। परिबीक्षा की इस अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिबीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिबीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिबीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिबीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किये गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। परन्तु उनका किसी भी समय ऐसे किसी भी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानांतरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (बी०) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा :-

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना द्वारा नियमित होती हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं --

- | | |
|-------------------------------|--|
| (i) सहायक निदेशक / अवर भविष्य | रु० 900-50-1,250 |
| (ii) अनुभाग अधिकारी | रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900 |
| (iii) सहायक | रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 |

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम-से-कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है।

(ग) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परिबीक्षा पर रखा जाएगा। परिबीक्षा की इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिबीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(घ) परिबीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिबीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(ङ) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी अन्य मंत्रालयों को स्थानांतरित नहीं किये जा सकते, जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी किए जा सकते हैं।

(छ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परिबीक्षाधीन अधिकारी भी) —

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य सम्भालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-अंगदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ज) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और मुविधा-टिकट-आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(झ) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किये गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

i (iii) भारतीय विदेश सेवा (बी०)

विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली तथा व्यापार मिशनों और केन्द्रों (पोस्ट्स) में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में शामिल किये गए

हैं। भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग में विभिन्न ग्रेड इस प्रकार हैं, इनमें ग्रेड IV से नीचे के ग्रेड शामिल नहीं हैं :—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालय में अवसर सचिव विदेश स्थित मिशन और केन्द्रों (पोस्ट्स) में प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900-50- 1200
एकीकृत ग्रेड I और ग्रेड III	मुख्यालय में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी, विदेश स्थित मिशन और केन्द्रों में कांसुल और रजिस्ट्रार।	रु० 350-25- 500-30- 590 रु० रो० 30-कु० रो० 30-830- 35-900
ग्रेड IV	मुख्यालय और विदेश स्थित मिशन केन्द्रों (पोस्ट्स) में सहायक	रु० 210-270 15-300 रु० रो० 15-450-कु० रो० 20-530

नोट 1 :—एकीकृत ग्रेड II और III तथा ग्रेड I में सीधे भर्ती की जाती है। एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को न्यूनतम वेतन 400 रु० प्रतिमास दिया जाता है।

नोट 2 :—समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों और आदेशों के अनुरूप ग्रेड के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के ज्येष्ठमान में पदोन्नत किया जा सकता है, जिसका वेतनमान रु० 900-50-1000-60-1600-50-1800 है।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के ग्रेड IV के लिये चुने हुए उम्मीदवार स्थायी और दीर्घकालीन अस्थायी खाली जगहों पर नियुक्त किये जाएंगे। ये नियुक्तियां, सामान्यतया, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों के योग्यताक्रम के अनुसार की जाएंगी, परन्तु जो उम्मीदवार विदेश सेवा के लिये योग्य नहीं होंगे, उनका नाम योग्यताक्रम में से निकाल दिया जाएगा। विदेश सेवा के लिये उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये उम्मीदवारों को एक चुनाव बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिये कहा जा सकता है जिसका गठन विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिबीक्षा पर रखे जाएंगे। परिबीक्षा की इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिबीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों पर तथा भारत के हाई कमीशन, लन्दन, में “स्थानीय संवर्ग” में कनिष्ठ सहायकों के ग्रेड में नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्तियों से भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवाएं ली जा सकती हैं।

5. भारत में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सदस्यों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो उनके समकक्ष पदों वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। विदेश में सेवा करते समय इन अधिकारियों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानों के अनुसार विदेश भत्ता, मुफ्त सुसज्जित निवास, बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता, सज्जा भत्ता (आउटफिट अलाउंस) और अपने लिये और अपने परिवारों

के लिये यात्रा-भाड़ा आदि की विशेष सुविधाएं मिल सकेंगी। ये सुविधाएं सरकार के सामान्य निर्णयों के अनुरार खत्म की जा सकती हैं या घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, ज्येष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 द्वारा तथा उन अन्य नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जिन्हें सरकार इसके बाद बनाए और सेवा पर लागू करे।

भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, ज्येष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 में दिए हुए उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

2. भारत के हाई कमीशन, लन्दन, में “स्थानीय संवर्ग” में कनिष्ठ सहायक।

(i) इस समय “स्थानीय संवर्ग” में नीचे लिखे पांच ग्रेड हैं :—

पद	वर्गीकरण
(क) कनिष्ठ सहायक	श्रेणी II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय
(ख) ज्येष्ठ सहायक	श्रेणी II (अराजपत्रित)
(ग) अधीक्षक	श्रेणी II (राजपत्रित) लिपिकवर्गीय
(घ) ज्येष्ठ अधीक्षक	श्रेणी I (राजपत्रित) गैर-लिपिकवर्गीय
(ङ) सहायक सचिव	श्रेणी I (राजपत्रित) गैर-लिपिकवर्गीय
वेतनमान	जीवन-निर्वाह भत्ता
रु० 200-15-440	रु० 400 प्रति मास
रु० 315-20-490 25-640-650	रु० 500 प्रति मास
रु० 500-30-710	रु० 600 प्रति मास
रु० 800-50-1150	रु० 700 प्रति मास
रु० 1000-50-1450	रु० 900 प्रति मास

नोट :—लन्दन में जीवन-निर्वाह भत्ता जीवन-निर्वाह सूचकांक के अनुसार घटना-बढ़ता रहेगा।

(ii) कनिष्ठ सहायकों के रूप में भर्ती किये गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिबीक्षा पर रखा जाएगा। परिबीक्षा की इस अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं (जिनमें हिन्दी की परीक्षा भी शामिल है) पास करनी होंगी। यदि परिबीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।

(iii) परिबीक्षा-अवधि समाप्त होने पर सरकार परिबीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, बशर्ते कि कोई मूल रूप से खाली जगह विद्यमान हो, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिबीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(iv) “स्थानीय संवर्ग” में नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को भारत के हाई कमीशन, लन्दन, में अथवा स्थानीय संवर्ग योजना में भाग लेने वाले यूनाइटेड किंगडम स्थित किसी भी कार्यालय में तैनात किया जा सकता है। भारतीय विदेश सेवा “बी०” केन्द्रीय सचिवालय सेवा अथवा अन्य किसी ऐसी सेवा में नियुक्ति का अधिकार उन्हें होगा जिसमें भर्तियां इस परीक्षा के आधार पर की जाती हैं।

(v) कनिष्ठ सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार इस संवर्ग के ऊँचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(vi) कनिष्ठ सहायकों के रूप में नियुक्ति के लिये भारत में भर्ती के लिये व्यक्ति अपने लिये और अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिये बम्बई से लंदन तक का पर्यटक दर्जे का यात्रा-भाड़ा पाने के अधिकारी होंगे। उन्हें इस आशय का एक बन्ध निष्पादित करना होगा कि वे कम-से-कम पांच वर्ष तक हार्ड कमीशन में सेवा करेंगे अथवा अपने ऊपर खर्च की गई यात्रा-भाड़े की उक्त रकम वापस लौटा देंगे। सेवा-निवृत्त होने पर वे सेवात यात्रा-भाड़ा (टर्मिनल पैसेज) पाने के भी अधिकारी होंगे।

(vii) इसके अलावा, वे 75 पौंड प्रतिवर्ष के हिमाब से एक नियत यात्रा-भाड़ा खाता रखने के अधिकारी होंगे। यह रकम उनके यात्रा-भाड़े के इस खाते में जमा की जाती रहेगी, जिसका उपयोग अधिकारियों और उनके परिवारों के केवल यात्रा-भाड़े के लिये ही किया जाएगा। अधिकारियों को दी जाने वाली रकम उनके खाते में इकट्ठी होती रहेगी, इसके लिये कोई सीमा नहीं रखी गई है, पर अधिकारियों के उक्त सेवा का छोड़ देने पर यह निधि व्ययगत (लैप्स) हो जाएगी।

(viii) कनिष्ठ सहायकों के रूप में नियुक्ति अविवाहित व्यक्ति 600 रु० और विवाहित व्यक्ति 1200 रु० उपस्कर के लिये पेशगी पाने के अधिकारी होंगे, पर यह रकम उन्हें वापस लौटानी होगी।

(ix) “स्थानीय संवर्ग” में शामिल पदों के लिये पेंशन तो नहीं मिलती है, पर अशदायी भविष्य निधि (भारत) योजना का लाभ मिलता है। इस निधि में सरकार का अंशदान उस राष्ट्रीय वेतनमान के 8 1/3 प्रतिशत की दर से निश्चित किया जाता है जो समकक्ष पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को भारतीय वेतन संरचना के अंतर्गत मिलता है। लेकिन, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होकर सेवा छोड़ने वालों को सरकार के उक्त अंशदान का लाभ केवल तभी मिल सकेगा जबकि उन्होंने पांच वर्ष तक लगातार सेवा की हो।

चुनाव आयोग, भारत

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 है। फिर भी, ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिबीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिबीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिबीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।

परिबीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिबीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिबीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊँचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे। इसके आगे के दो और ऊँचे ग्रेड ये हैं :—

1. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—

रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900।

2. अवर्ग सचिव ग्रेड—रु० 900-50-1250।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1965

सं० 30 (1)/64-टैक्नी०—भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 30 (1)/64-टैक्नी०, दिनांक 30 अप्रैल 1964 को तर्जुमी करते हुए भारत सरकार, तेल सलाहकार समिति की सदस्यता में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (i) श्री के० आर० दामले के स्थान पर श्री पी० आर० नायक, सचिव, पेट्रोलियम विभाग, (पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली की नियुक्ति।
- (ii) श्री आर० प्रसाद के स्थान पर श्री नकुल सेन, सचिव, रसायन विभाग (पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली की नियुक्ति।
- (iii) श्री एन० एन० कश्यप के स्थान पर श्री एस० के० गुहा, मह-सचिव, पेट्रोलियम विभाग (पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली की नियुक्ति।
- (iv) इण्डियन आयल कम्पनी लि० के चेयरमैन के स्थान पर इण्डियन आयल कार्पोरेशन (मार्केट प्रभाग) के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति।
- (v) भारतीय शोधनशालाएं लि० के प्रबन्ध निदेशक के स्थान पर इण्डियन आयल कार्पोरेशन (शोधनशालाएं प्रभाग) के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति।
- (vi) श्री राज कुलकर्णी, प्रधान सचिव, पेट्रोलियम श्रमिक के राष्ट्रीय मण्डल-संघ, 27, मिलिटरी स्क्वेयर लेन, फोर्ट, बम्बई (नई नियुक्ति)।

एस० सुन्दरराजन, अवर्ग सचिव

स्वास्थ्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1965

सं० प० एफ० 10-12/64-सी० एण्ड सी० डी०—यह सर्व-विदित है कि चूहे तथा अन्य कृन्तक खेतों, फसलों और बाग-वगीचों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं और कृषि संबंधी उत्पादों जिनमें वे अनाज भी सम्मिलित हैं जो मनुष्यों के खाने के लिये जमा किये जाते हैं, को भी हानि पहुंचाते हैं। बांधों में चूहों के बिलों से सिंचाई के पानी की भी काफी हानि होती है। आर्थिक हानि के अतिरिक्त चूहे अनेक प्रकार के रोग भी फैलाते हैं जिनमें प्लेग सबसे भयंकर रोग है। भले ही यह रोग अब भारत में उतना नहीं रहा जितना यह पहले रहता था फिर भी यहां इसके केन्द्र हैं ही और चूक खाद्यान्नों और अन्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाना चलता ही है, अतः हो सकता है इससे आम बीमारी फैल जाय। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए इन हानियों और खतरों को समाप्त करना बांछनीय है। कृन्तक नियंत्रण के पर्याप्त उपाय खोजने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार करती आ रही है। स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् ने 10 मे 12 फरवरी 1965 को बम्बई में हुई अपनी अन्तिम बैठक में समन्वित तथा दीर्घकालीन कृन्तक नियंत्रण उपायों के अभाव पर चिन्ता व्यक्त की तथा इस दिशा में प्रभावकारी उपाय बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। इस परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने कृन्तक नियंत्रण की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है।

समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

- | | |
|---|------------|
| (1) स्वास्थ्य उप-मंत्री | अध्यक्ष |
| (2) श्री डी० पी० सिंह, संयुक्त सचिव, योजना आयोग | सदस्य |
| (3) डा० बनवारी लाल, निदेशक, (स्वास्थ्य) रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय | सदस्य |
| (4) कर्मल बरकत नारायण, सलाहकार (स्वास्थ्य) सामुदायिक विकास मंत्रालय | सदस्य |
| (5) डा० एम० बी० पिगले, निदेशक, (संग्रह एवं निरीक्षण) खाद्य विभाग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय | सदस्य |
| (6) परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (7) श्री एम० सी० सेन गुप्त, संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग | सदस्य |
| (8) डा० एम० पी० रामकृष्णन, निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली | सदस्य-सचिव |

2. निर्देश पद इस प्रकार होंगे :—

- (1) देश के किन-किन भागों में चूहों के कारण फैलने वाले रोगों का खतरा है तथा चूहों से कितनी हानि होती है इसका सर्वेक्षण करना;
- (2) वर्तमान संगठनों तथा उनकी पर्याप्तता और इस कार्य के लिये कृत्तक नियंत्रण के लिये बरते गए उपायों, उनकी कमियों और त्रुटियों का सर्वेक्षण;
- (3) यह देखना कि क्या इस समस्या के हल के लिये विभिन्न अधिनियमों में वर्तमान कानूनी व्यवस्था पूरी है या नहीं तथा इस संबंध में क्या संशोधनों अथवा नए विधान की आवश्यकता है या नहीं, इस पर विचार करना;
- (4) एक समन्वित तथा दीर्घकालिक कृत्तक नियंत्रण कार्यक्रम के लिये उचित संगठनात्मक मशीनरी एवं आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देना, साथ ही यह बतलाना कि इसके आर्थिक आशय क्या होंगे, कृत्तक

नियंत्रण के एक सामान्य कार्यक्रम को चयनित तथा संगठित करने के लिये कोतसी एजेन्सी अनुकूलतम होंगी।
(5) इस सम्बन्ध में संगत समझा जाने वाला कोई अन्य विषय।

3. उस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु यह राज्यों का दौरा कर सकती है और राज्य सरकारों तथा निगमों के उपयुक्त प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में अन्य ऐसे अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

5. सम्भवतया समिति 30 जुलाई 1965 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

आपदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, संसदीय मामलों के विभाग, लोक सभा सचिवालय, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति जी के निजी एवं सैनिक सचिवों, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

र० क० रामध्यानी, सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1965

शुद्धि-पत्र

सं० डब्ल्यू० बी०-21 (11)/65-13 मार्च 1965 के भारत के राजपत्र के भाग 1, अनुभाग 1 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के संकल्प संख्या डब्ल्यू बी०-21 (16)/64, तारीख 22 फरवरी 1965 के परिशिष्ट में निम्न-लिखित संशोधन किया जाएगा :—

“ह०/-आई० डी० दास गुप्त” और “टी० के० नाम्बियार” के स्थान पर

“ह०/-आई० बी० दास गुप्त” और “टी० के० परमेश्वरम” पढ़िए।

बी० आर० सेठ, उप सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 1st May 1965

No. 3(1)EC/65.—The Speaker has been pleased to appoint Shri Arun Chandra Guha as Chairman of the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April 1966.

No. 3(1)EC/65.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April 1966 :

1. Shri Bhagwat Jha Azad.
2. Shri Dinen Bhattacharya.
3. Shri C. K. Bhattacharya.
4. Shri Brij Raj Singh—Kotah.
5. Shri Jagannath Rao Chandriki.
6. Shri Chuni Lal.
7. Shri R. Dharmalingam.
8. Shri Digambar Singh Chaudhri.
9. Shri Arun Chandra Guha.
10. Shri Indrajit Gupta.
11. Shrimati Jamuna Devi.
12. Shri Naryan Sadoba Kajrokat.
13. Shri Gauri Shanker Kakkar.
14. Shri C. M. Kedaria.
15. Shri L. D. Kotoki.
16. Shri Narendrasingh Mahila.
17. Shri Dwarka Dass Mantri.
18. Shri Jaswantraj Mehra.
19. Shri Mahesh Dutta Misra.

20. Shri Mohan Swarup.
21. Chowdhry Ram Sewak.
22. Shri B. Rajagopala Rao.
23. Shri J. Ramapathi Rao.
24. Shri P. G. Sen.
25. Shri H. Siddananjappa.
26. Shri Nardeo Snatak.
27. Shri N. M. R. Subbaraman.
28. Shri Ramchandra Ulaka.
29. Shri Vishram Prasad.
30. Shri Yudhvir Singh.

AVTAR SINGH RIKHY, Dy. Secy.

SUPREME COURT OF INDIA

CIRCULAR MEMORANDUM

New Delhi, the 22nd April 1965

SUBJECT :—Annual Summer Vacation—1965.

No. F.44/65-S.C.A.-(G).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court of India will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 10th May 1965 to Sunday, the 18th July 1965 (both days inclusive) and will reopen on Monday, the 19th July 1965.

The Offices of the Court will, during the vacation, be open every day except on Saturdays and Gazetted holidays and the hours of work will be from 8 A.M. to 12-30 P.M. but

the hours may be extended whenever necessary. On the days when the Court sits, the hours of work will in any case be from 10 A.M. to 4 P.M.

During the Vacation all important communications which are intended for the Supreme Court of India and are not delivered at the Registry during office hours, may be sent to the residence of Shri S. K. Gupta, Assistant Registrar, at 32-C, Havelock Square, New Delhi-1, unless and until notified otherwise. No telegrams may, however, be delivered between the hours 10 P.M. and 6 A.M.

Y. D. DESAI, Registrar.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 8th May 1965

No. 6/1/65-C.S.(A).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in December, 1965, for the purpose of filling vacancies in the following Services/post are published for general information :—

- (i) Central Secretariat Service—Assistants' Grade;
- (ii) Indian Foreign Service (B)—Grade IV (Assistants);
- (iii) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants);
- (iv) Posts of Junior Assistant in the "Local Cadre" in the High Commission of India, London.

NOTE.—In addition to the Services/post mentioned above, some appointments on the results of this examination may, also be made to posts of Assistants in certain Offices not included within the purview of any of these Services, e.g., Election Commission, Department of Tourism, Department of Parliamentary Affairs, Intelligence Bureau.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim, or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan, or
- (e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India;

provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been granted by the Government of India and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade IV.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being granted in his favour by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Andaman and Nicobar Islands or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a repatriate from Ceylon or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and

Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1965 i.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1941 and not later than 1st August, 1945.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at one stage or another;
- (iii) up to a maximum of four years if a candidate is a resident of Andaman and Nicobar Islands;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
- (vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964; and
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. (a) A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

(b) In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not the above qualification as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

(c) Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examinations. Such a candidate will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(c) Women candidates who are married will not ordinarily be eligible for appointment to Grade IV of the I.F.S.(B). A woman member of this Grade who is not married shall obtain

the permission of the Government, in writing, before her marriage is solemnised. At any time, after the marriage, a woman member of the Service may be required to resign from the service, if the Government is satisfied that her family and domestic commitments are likely to come in the way of the due and efficient discharge of her duties as a member of the Service.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice. No claim for a refund of the fee will be entertained except to the extent stated in that Annexure, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service/post.

NOTE 1.—Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application (c.f. Col. 27 of the application form) but a candidate may be assigned to any Service/post for which the examination is held.

NOTE 2.—The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

19. Candidates will be required to pass a test in type-writing conducted by the Commission, at a minimum speed of 30 words per minute, within a period of two years from

the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

20. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, the Railway Board Secretariat Service, the Indian Foreign Service (B), posts of Junior Assistants in the "Local Cadre" in the High Commission of India, London and the posts of Assistants in the Election Commission of India, are briefly stated in Appendix III.

K. THYAGARAJAN, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India.

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational Institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act (1956).

University in Burma

The University of Rangoon.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Eddinburg, Glassgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Dublin, The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The Dacca University, The University of Sind, The Rajshahi University.

APPENDIX I-A

The following qualifications have also been recognised by the Government of India as equivalent to the corresponding degrees indicated against each :—

Particulars of the qualifications	Equivalent degree recognised
1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalyaya Kangri, Hardwar.	Bachelor of Arts
2. Jamia Sanaid of Jamia Milia Islamia, Delhi.	Do.
3. Shastri of Kashi Vidyapith, Banaras,	Do.
4. French Examination "Baccalaureat".	Do.
5. French Examination "Propeudeutique".	Bachelor of Arts or Science.
6. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.	Bachelor of Arts.
7. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.	Do.
8. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.	Bachelor of Commerce.
9. Diploma in Civil Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Technical Education.	Degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering, as the case may be.
10. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines and Allied Geology, Dhanbad.	Bachelor of Science Honours Degree in Mining.
11. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".	Bachelor of Arts or Science.

N.B.—(1) The recognition of the qualifications mentioned against items 1 to 3 above is valid up to 17th September, 1965.

(2) The recognition of the qualification mentioned against item 4 above is provisional.

APPENDIX II

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

	Max. Marks	Time allowed
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India.	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer paper 1 and paper 4 either in Hindi or in English. Paper 2 and paper 3 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 7 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects at the examination.

6. From the marks assigned to candidates in each subject such deduction will be made as the Commission may consider necessary in order to ensure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible hand-writing.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

2. General English :

(i) *Precis writing and drafting* : Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) *questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.*

(iii) *Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.*

NOTE.—In paper 2, questions on *precis writing* will carry 75 marks, *drafting* 75 marks and those on *grammar, idioms, etc.* 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

3. Arithmetic :

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The questions will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

4. General Knowledge including Geography of India :

Knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on Indian History of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(1) (i) Central Secretariat Service.

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows:—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade 1 (Under Secretary or equivalent)—Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers' Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants' Grade—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) Railway Board Secretariat Service.

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as recruitment, training, promotion etc., are concerned, are regulated by the Railway Board's Secretariat Service Scheme, which is similar to the Central Secretariat Service Scheme.

(b) The Railway Board Secretariat Service consists of the following grades:—

(i) Assistant Director/Under Secretary—Rs. 900—50—1,250.

(ii) Section Officer—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iii) Assistants—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(c) Officers recruited direct as Assistants will be on probation for two years during which they will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationer from service.

(d) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) The Railway Boards' Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(g) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(h) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(i) As regards leave and other conditions of service staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) Indian Foreign Service (B)

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900—50—1, 250.
Integrated Grade II & III.	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and posts abroad.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions/Posts abroad.	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE 1.—Direct Recruitment is made to the integrated Grades II and III and to Grade IV. Assistants promoted to the integrated Grades II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

NOTE 2.—In accordance with the rules and orders in force from time to time, Grade I officials may be promoted to the Senior Scale of the Indian Foreign Service carrying a scale of pay of Rs. 900—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

2. Candidates selected for Grade IV of the IFS(B) will be appointed against permanent and long term temporary vacancies. Appointments will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission, subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad, candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, the Railway Board Secretariat Service and the grade of Junior Assistants in the "Local Cadre" in the High Commission of India, London. Further, all such persons will be liable to service in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc. according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All officers appointed to the I.F.S.(B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre of the I.F.S.(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

Junior Assistant in the "Local Cadre" in the High Commission of India, London.

(i) The "Local Cadre" has at present five grades as follows :—

Designation	Classification	Scale of Pay	Cost of living allowance
(a) Junior Assistant.	Class II (non-gazetted) (Ministerial)	200—15—400	Rs. 400 p.m.
(b) Senior Assistant.	Class II (non-gazetted)	350—20—490—25—640—10—650.	500 p.m.
(c) Superintendent.	Class II (Gazetted) Ministerial.	500—30—710	600 p.m.
(d) Senior Superintendent.	Class I (Gazetted) non-Ministerial.	800—50—1150	700 p.m.
(e) Assistant Secretary	Class I (Gazetted) non-ministerial.	1000—50—1450.	900 p.m.

Note: The cost of living allowance is likely to vary according to the Cost of living Index in London.

(ii) Persons recruited as Junior Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests (including examination in Hindi) as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(iii) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment, subject to availability of substantive vacancy, or, if his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may deem fit.

(iv) Junior Assistants appointed to the "Local Cadre" will be posted to the High Commission of India, London or to any of the Offices in the United Kingdom participating in the Local Cadre Scheme. They will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Indian Foreign Service 'B', the Central Secretariat Service or to any other service for which recruitments are made through this examination.

(v) Junior Assistants will be eligible for promotion to the higher grades in the Cadre in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(vi) Persons recruited in India for appointments as Junior Assistants will be entitled to tourist class passage from Bombay to London for themselves and their families (wife and children). They will be required to execute a Bond that they will serve in the High Commission for a minimum period of five years or refund the amount of money spent on their passages. They will also be entitled to terminal passages to India on retirement.

(vii) In addition they will be entitled to a fixed passage account @ £ 75 p.a. which will be paid into their passage-accounts to be utilised only for the cost of passages of the officers and their families. The above grant may be accumulated without limit except that the fund shall lapse when the officers leave the Service.

(viii) Persons appointed as Junior Assistants will be entitled to a repayable advance for equipment @ Rs. 600 in the case of unmarried persons and Rs. 1,200 in the case of married persons.

(ix) Posts included in the "Local Cadre" are not pensionable but carry the benefit of the Contributory Provident Fund (India) Scheme. Government contributions to the Fund will be fixed at the rate of 8 1/3% of the notional salary of the Central Government officers holding comparable posts in the Indian pay structure. However, five years' continuous service shall be a prerequisite before Government contributions become available to those leaving service on voluntary retirement.

3. Election Commission, India

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons

appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) *Section Officers' Grade*—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(2) *Under Secretaries' Grade*—Rs. 900—50—1,250.

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

RESOLUTION

New Delhi, the 27th April 1965

No. 14/5/64-SCT.II.—In pursuance of the recommendation made by the Central Advisory Board for Harijan Welfare, the Government of India have decided to constitute a Committee to examine the question of Untouchability as also the problem of Economic Uplift of Scheduled Castes.

2. The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Shri L. Elayaperumal, M.P. (Madras).

Members

2. Shri C. Das, M.P. (Andhra Pradesh).

3. Shri R. Achuthan, M.P. (Kerala).

4. Shri B. K. Gaikwad, M.P. (Maharashtra).

5. Shri P. L. Majumdar, President, Gujarat Harijan Sevak Sangh, Ahmedabad (Gujarat).

6. Shri Narain Din (Uttar Pradesh).

7. Shri V. V. Vaze, Deputy Legal Adviser, Ministry of Law.

3. Shri S. K. Kaul, Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Jaipur, will be the Secretary to the Committee.

4. The Committee will have powers to coopt more members as and when necessary. The Committee will meet at such intervals as the Chairman may decide.

5. The Committee may visit or depute one or more of its Members to visit such parts of India as it considers necessary. The Chairman, Members and Coopted Members will be entitled to travelling allowances and daily allowances in accordance with the Ministry of Finance Memorandum No. F.6(26)-EIV/59, dated the 5th September, 1960 as amended from time to time.

6. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

- (i) to study the various aspects of untouchability, in particular the working of the Untouchability (Offences) Act, 1955, and the restrictions, if any, imposed on the entry of Harijans into public places of worship, and to suggest remedial measures; and
- (ii) to study the problem of the economic uplift of the Scheduled Castes, evaluate the impact of the present schemes, and make recommendations as to the further measures that may be necessary.

7. The Committee will submit its report within a period of six months.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH

RESOLUTION

New Delhi, the 29th April 1965

No. F. 10-12/64-C&C.D.—It is well known that rats and other rodents consume and cause severe damage to field, garden crops and orchards and infest agricultural products including grains which are stocked for human consumption. The loss caused to the irrigation water by rat burrows in the embankments is also considerable. In addition to the economic losses, the rats also spread a variety of human diseases the worst of which is plague. Although this disease is not as common as it used to be in India, foci still exist and in view of the movements of foodgrains and other commodities may give rise to a general outbreak. It is, therefore, desirable to eliminate these losses and risks and the question of devising adequate rodent control measures has been under consideration of the Government of India. The Central Council of Local Self Government at its last meeting held at Bombay from the 10th to 12th February 1965, expressed concern over the lack of coordinated, sustained rodent control measures and stressed the need for taking effective measures in this direction. In pursuance of the recommendations made by the said Council, the Government of India have decided to constitute a committee to consider the problem of rodent control in all its aspects. The Committee shall consist of :—

Chairman

1. Deputy Minister for Health.

Members

2. Shri D. P. Singh, Joint Secretary, Planning Commission.

3. Dr. Banwari Lal, Director, (Health), (Railway Board), Ministry of Railways.

4. Col. Barkat Narain, Adviser (Health), Ministry of Community Development & Cooperation (Deptt. of Community Development.)

5. Dr. S. V. Pingale, Director, (Storage & Inspection), (Department of Food), Ministry of Food & Agriculture.

6. Representative of the Ministry of Transport.

7. Shri S. C. Sen Gupta, Joint Secretary, Deptt. of Social Security, New Delhi.

Member-Secretary

8. Dr. S. P. Ramakrishnan, Director, National Institute of Communicable Diseases, Delhi.

2. The terms of reference shall be :—

- (i) To survey the extent of exposure of the country to the risk of disease and the loss caused by rodents.
- (ii) To survey the existing organisations & their adequacy and the measures taken for rodent control for the purpose, the deficiencies and defects.
- (iii) To examine whether the existing legislative provisions in various Acts are adequate to cope with the problem and amendments or fresh legislation which may be necessary in this regard.
- (iv) To suggest suitable organisational machinery and necessary measures for a coordinated and sustained rodent control programme together with the financial implications, the manner in which a programme of rodent control can be financed and the agency which would be best suited to organise and administer a general programme of rodent control.
- (v) Any other matter considered relevant in this connection.

3. The headquarters of the Committee will be in New Delhi but it may visit States on tour and coopt suitable representatives of State Governments or Corporations.

4. The Committee will hold its meetings as and when necessary and may invite to its meetings such other officers as may be considered necessary.

5. The Committee may submit its report by the 30th July 1965.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Directorate General of Health Services, All Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Cabinet Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission for information.

R. K. RAMADHYANI, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

New Delhi, the 27th April 1965

No. F. 17-7/63SEU.1.—In partial modification of the Government of India, Ministry of Education Resolution No. 17-7/63-SW.1, dated the 20th November 1963, substitute Clause 15 by the following :—

"15. No act or proceeding of the Board or a Committee appointed by it shall be invalidated merely by reason of existence of a vacancy or vacancies among the members; the quorum of a Board meeting shall be 2/5th of the total membership."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Delhi Library Board for circulation among its members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. O. JOSHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 27th April 1965

No. 60Elec/240/3.—It is hereby notified for the general information of all users of Railway lines and premises situated on the completed section of the undernoted section of the Northern Railway that the 25,000 volts 50 cycles A.C. overhead traction wires will be energised on or after the date specified against the section. On and from the same date the overhead traction line shall be treated as live at all times and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the said overhead line :

Mughalsarai—Subedarganj—28th Feb. 1965.

P. C. MATHEW, Secy.
Railway Board.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th April 1965

No. WB-21(11)/65.—In the Appendix to the Resolution of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment Resolution No. WB-21(16)/64 dated the 22nd February, 1965 published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 13th March 1965, the following corrections shall be made :—

For "Sd/- I. D. Das Gupta" and "T. K. Nambiar".

Read "Sd/- I. B. Das Gupta" and "T. K. Parameswaram Nambiar".

B. R. SETH, Dy. Secy.